भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1590
31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन हेतु कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भरता

1590. श्री राघव चड्ढाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस्पात उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ख) सरकार द्वारा घरेलू कोकिंग कोयला उत्पादन और कोयला धुलाई संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) वैकल्पिक रूप से हाइड्रोजन-आधारित इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या योजना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) साझेदार देशों के साथ कोकिंग कोयले की दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधी समझौते सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, और कंपनियां प्रौद्यो-वाणिज्यिक विचारों के आधार पर स्त्रोत निर्धारण संबंधी निर्णय लेती हैं। तथापि, सरकार की निम्नलिखित पहलों का उद्देश्य कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ावा देना, वाशरी क्षमता में वृद्धि करना और इस्पात उत्पादन के लिए भारत की आयात निर्भरता को कम करना है:-

i. सरकार ने घरेलू कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने और कोल वाशिंग की क्षमता में वृद्धि के लिए 2021 में "मिशन कोकिंग कोल" शुरू किया है।
ii. सरकार ने कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है।
iii. घरेलू कोकिंग कोल के सम्मिश्रण को बढ़ाने के लिए स्टाम्प चार्ज बैटरियों को बढ़ावा देना।

(ग) सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए चार (04) पायलट परियोजनाएं प्रदान की हैं।

(घ) आपूर्ति जोखिमों को कम करने और आपूर्ति सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने आयात स्रोतों के विविधीकरण सहित उपाय किए हैं और दीर्घकालिक कोकिंग कोल आपूर्ति के लिए देशों के साथ सहमति ज्ञापन भी किए हैं।

*****